21 मार्च, 2016

यमन संकट

जेठू एल्ज़ा चेरियन चाको

पश्चिम एशिया के संकट पर चर्चा करते हुए , सीरियाई शरणार्थी संकट और आईएस ने मुखपृष्ठ की सुर्खियां और टेलीविजन कवरेज को बटोर रहा है। इस क्षेत्र में एक ऐसे ही प्रहसन का खुलासा हुआ है, वह है यमन। यमन की स्थिति, जो एक मानवीय संकट में तब्दील हो गई है , कई कोणों से इसके अध्ययन का समर्थन करता है। क्षेत्रीय राजनीति दो समूहों में विभाजित है, जिनमें से हर कोई वैध सरकार होने का दावा करता है- एक हौथियों के नेतृत्व में (जिसे अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है) और दूसरा राष्ट्रपति हैदी के नेतृत्व में ; शियाओं और सुन्नियों के बीच धार्मि क विच्छेद, जिसमें न केवल स्थानीय ; बल्कि सऊदी-ईरान तनाव के साथ क्षेत्रीय आयाम भी हैं; भू-रणनीतिक प्रभाव, जो यमन के वैश्विक समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण बिंदु है ; संयुक्त राष्ट्र की मानवी य संकट को सम्मिमलित करने में इस की भूमिका; और वैश्विक शक्तियों (मिसाल के तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन) की भूमिका संकट में है। यमन का मामला ऐसा भी है जो अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी की बस याद दिलाता है।

क्यों खास है यमन?

इस तथ्य के बावजूद कि यम न 'दुनिया को हिला देनेवाला' तेल उत्पादक देश नहीं है , बल्कि रणनीतिक रूप से यह देश जहां पर स्थित है भू- राजनीतिक उस लिहाज वह स्थिति दिलचस्प है। सऊदी अरब के साथ सुराखदार लंबी सीमा के साथ यमन में बंदरगाह (जैसे अदन) हैं, जो दुनिया के कुछ व्यस्त तम

समुद्री मार्गों में से एक हैं। यमन ने भी फारस की खाड़ी के सिरे पर एक समुद्री मार्ग का अवरोध बिंदु बाब अल मांडब जलडमरूमध्य पर नजर रखे हुए हैं। इस प्रकार, यमन के अस्थिरता क्षेत्र में नौवहन को और अधिक असुरक्षित बनाने के लिए अपने लंबे और बिखरी आबादी वाले समुद्र तट का उपयोग क रके समुद्री डाकू की संभावना का द्वार खोलती है।[1]

बढ़ती अस्थिरता के साथ अरब प्रायद्वीप (एक्यूएपी) और इस्लामिक स्टेट (आईएस) में अल-कायदा ने अपनी पहुंच का विस्तार किया है और यह यमन के पड़ोसी, सऊदी अरब और ओमान के लिए एक समस्या है, जिसके साथ वह सीमा साझा करता है। इस प्रकार, सऊदी अरब और ओमान दोनों के लिए स्थिर पड़ोस समय की जरूरत है।

स्रोत: गुगल[2]

यमन के स्थिर होने का एक और कारण आव्रजन संकट है। हालांकि यमन एक छोटा- सा देश है, लेकिन दुनिया में इसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। चल रहे गृह युद्ध के कारण पेट्रो लियम

उत्पादन और निर्यात में गिरावट आई है , जिससे पहले से ही बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था अब चरमराने लगी है। इसने यमन के लोगों को दूसरे अरब देशों में जाने के लिए प्रेरित किया है। सऊदी अरब और ओमान को अवैध आव्रजन और सीमा पार मानव तस्करी के एक बड़े खतरे का सामना क रना पड़ता है। लेकिन एक दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि इन देशों , विशेष रूप से सऊदी अरब और ओमान का सामना करने वाली आप्रवासन समस्या सिर्फ यमनी नागरिकों से जुड़ी नहीं है ; बल्कि सोमालिया और इथियोपिया जैसे अस्थिर देशों के अवैध प्रवासियों और चरमपंथियों से भी जुड़ी हुई है।[3] यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यमन में न तो शरणार्थियों से संबंधित कोई राष्ट्रीय कानून है और न ही शरणार्थी की स्थिति का निर्धारण करने के लिए कोई तंत्र है। संघर्ष के पैमाने और तीव्रता ने हजारों की संख्या में गैर-दस्तावेजी, फंसे हुए प्रवासियों को बुनियादी संसाधनों और देखभाल से वंचित कर दिया है। इन सभी कारकों ने तस्करी और मानव तस्करी करनेवाले गिरोहों को यमन में सक्रियता के साथ अपना काम करने को प्रोत्साहित किया है।[4]

सऊदी अरब के साथ अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी के लिए कितना महत्वपूर्ण है , यमन इसकी भी याद दिलाता है। क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका को एक सामरिक साझेदार के रूप में सऊदी अरब की आवश्यकता है ; ताकि अमेरिका आईएस के खिलाफ युद्ध पर ध्यान केंद्रित कर सके। लेकिन इसीके साथ आरोप यह भी है कि यमन पर सऊदी अरब द्वारा की गयी बमबारी मानव पीड़ा का कारण बना; दोनों पक्षों के हवाई हमलों, खासतौर पर ताईज़ में एमएसएफ अस्पताल की बमबारी के बाद; की आलोचना मानवीय संकट के रूप में की गई है। हौथी समर्थकों ने आरोप लगाया है कि सऊदी गठबंधन के टकराव की स्थिति में प्रवेश करने के बाद यहां लगभग 6000 लोग (और उनमें से आधे नागरिक थे) मारे गए हैं। हौथी सैन्यबल के अनुसार अरब प्रायद्वीप क्षेत्र में बढ़ते ईरानी प्रभाव को देखते हुए उन पर महज नियंत्रण के लिए सऊदी अरब ने इस संघर्ष में प्रवेश किया।[5] उल्लेखनीय है कि जब उनका ध्यान अल-हजम स्टॉर्म के सैन्य संचालन पर गया तो संयु क्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने क्षेत्रीय राष्ट्र-राज्यों से कहा कि "वे यमन की एकता, संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को कम करने वाली किसी भी तरह की कार्रवाई से बचें।"[6]

यमन संकट का एक और पहलू यह है कि संयुक्त राष्ट्र के अलावा अमेरिका , रूस और ब्रिटेन जैसी अंतरराष्ट्रीय शक्तियां खुद को (सीरिया के विपरीत) शामिल करने से हिचकिचाती हैं। मानवीय संकट और हिंसक जिहादी समूहों (जैसे अल-कायदा के यमनी फ्रैंचाइज और इस्लामिक स्टेट) के अनियंत्रित

विस्तार के बावजूद , ये देश संघर्ष की आवश्यकता , अवधि और परिणामों को लेकर सशंकित हैं। इन आशंकाओं में बदलाव जरूरी है , विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट के अनुसार , यमन के सामने आने वाले अधिकांश मानवीय संकट अंधाधुंध बमबारी और संघर्ष में 'शामिल दलों द्वारा अंधाधुंध गोलाबारी'[7] के कारण हैं ; इसका मतलब यह है कि संकट के लि ए जिम्मेदार दोनों पक्षों को आजीविका , घरों, समुदायों और आवश्यक नागरिक सुविधा की संरचना को नष्ट करने और नागरिकों की हत्या करने के लिए दोषी ठहराया जाता है।

यमन जिस संकट का सामना कर रहा है , उसी के मद्देनजर इस संकट के कारण पर विचार करते हैं। हालांकि यमन संक ट के विभिन्न आयाम हैं और उनमें से प्रत्येक कारण पर विचार करने के लिए अन्य कारकों को भी ध्यान में रखना होगा।

संघर्ष के विभिन्न रंग:

- <u>राजनीतिक अस्थिरता:</u>

  2011 में अरब स्प्रिंग के एक हिस्से के रूप में यमन ने भी तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह (जनवरी 2011) के शासन के खिलाफ एक 'विद्रोह' किया था। बहुत फ़जीहत होने के बाद 23 नवंबर 2011 को सालेह खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी), जो जीसीसी पहल कहलाता है , द्वारा भंग किए गए 'संक्रमण समझौते' की शर्तों के तहत कार्यालय छोड़ने के लिए सहमत हुए । राष्ट्रपति की सत्ता को अब्दो रब्बो मंसूर हादी, जो उप-राष्ट्रपति थे; को (आपराधिक अभियोजन से प्रतिरक्षा के बदले में) स्थानांतरित किया गया था। मार्च 2012 में राष्ट्रीय संवाद सम्मेलन (एनडीसी) शुरू किया गया था। एनडीसी का इरादा संक्रमणकालीन बातचीत प्रक्रिया के रूप में यमनी संकट के सुलह प्र यासों में मदद का था। हालांकि, एनडीसी के भीतर दो हौथी प्रतिनिधियों की हत्या से हौथी जनजाति और सरकारी तत्वों के बीच शत्रुता भड़क गयी। इस कारण जनवरी 2014 तक एनडीसी समाप्त हो गया।

  इस बीच सालेह ने हादी सरकार के खिलाफ लोकप्रि य असंतोष का लाभ उठाया और अपनी पार्टी, जनरल पीपुल्स कांग्रेस (जीपीसी) के माध्यम से राजनीतिक तौर पर वापसी के लिए अपने सामान्य दुश्मनों के खिलाफ हौथियों के साथ खुद को संबद्ध कर लि या। हौथी सरकार की सीट सनाया की ओर आगे बढ़े और इस पर कब्जा कर लिया। पूर्व राष्ट्रपति सालेह और हौथी सेना के

दो कमांडरों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की यमन प्रतिबंध समिति द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। [8] राजनीतिक और नागरिक आवाजाही को पटरी पर लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मध्यग समझौते के बावजूद, सत्ता और क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हौथियों ने संघर्ष को और तेज कर दिया। जनवरी 2015 तक राष्ट्रपति हादी को अपने प्रधानमंत्री पद और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। अब्देल मलिक अल- हौथी के अधीन हौथियों ने यमन सरकार पर अपना नियंत्रण घोषित किया। उनके अनुसार हौथियों ने 'शानदार क्रांति' के माध्यम से सत्ता पर कब्जा कर लिया था; इसके विपरीत, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुदाय ने इसे 'तख्तापलट' कहा, क्योंकि अभी भी यूएन और जीसीसी की नजर में राष्ट्रपति हादी यमन के वैध प्राधिकारी थे।

- <u>धार्मिक टकराव:</u>

हौथी आंदोलन अपनी जड़ें एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन का रुक लेता है जो यमन में ज़ैद (शिया) मान्यताओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उभरा। यमन के उत्तरी भाग में बढ़ती सुन्नी या सलाफी प्रभाव की यह एक प्रतिक्रिया थी। यमन की लगभग 45 प्रतिशत आबादी शिया है और वे यमन के उत्तर में , मुख्यतया सना या के आसपास संकेंद्रित हैं। [9] इन दोनों के साथ- साथ एक इस्लामिक पार्टी अल-इस्लाह का भी विकास हुआ। अब , अल-इस्लाह, या यमनी कॉन्ग्रेशन फॉर रिफ़ॉर्म, यमन में सबसे बड़ी इस्लामवादी पार्टी है। मुख्यतया सुन्नी , इसने आधिकारिक विपक्ष और सरकार के सहयोगी दोनों के रूप में काम किया है।

हालांकि हौथी आंदोलन ने जीसीसी पहल में कोई भूमिका नहीं निभाई, लेकिन इसने एनडीसी में भाग लिया। इसने अपने पारंपरिक आधार से परे अपनी राजनीतिक अपील को मजबूत किया। हालांकि एनडीसी का मुख्य सुझाव यह है कि यमन को छह संघीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए,[10] जिसका हौथी समर्थकों द्वारा विरोध किया गया था ; उन्हें डर यह था कि यह उनके क्षेत्रीय पावरबेस को कम कर देगा।

इस घरेलू गतिरोध के अलावा सऊदी सरकार ने यह आरोप लगाया कि हौथी को ईरान का समर्थन प्राप्त हैं। हालांकि ईरान में हौथी एक अलग शिया संप्रदाय से आते हैं , लेकिन इस तरह के आरोप विभाजन और सांप्रदायिक बयानबाजी भर के लिए हैं। इस प्रकार यमन में इस संघर्ष न केवल एक धार्मिक मोड़ ले रहा है ; बल्कि यह दुनिया के प्रमुख सुन्नी राष्ट्र (सऊदी अरब) और उसके शिया विरोधी (ईरान) के बीच लड़े जा रहे एक छद्म युद्ध जैसा नजर आ रहा है। यमन में

चरमपंथी समूहों का भी खतरनाक विस्तार हुआ है। हौथी-हादी संघर्ष की वजह से सुरक्षा के मद्देनजर वैक्यूम का लाभ एक्यूएपी और आईएस जैसे समूह उठा रहे हैं। उन्होंने यमन के बहुमत (55 प्रतिशत से अधिक) सुन्नी आबादी के बीच शिया हौथियों के प्रति आक्रोश पैदा करने के लिए संघर्ष का इस्तेमाल किया है।[11] एक्यूएपी ने उत्तर-दक्षिण विभाजन का इस्तेमाल संप्रदायवाद को बढ़ावा देने के लिए भी किया है , वहीं आईएस ने विशेष रूप से हौथी शिया मस्जिदों को निशाना बनाते हुए कई आत्मघाती हमले किए। संक्षेप में , अल-कायदा और आईएस आंदोलन, दोनों ही हौथी समर्थकों से लड़ने के लिए दृढ़-संकल्प हैं और क्षेत्र पर दावा करने के लिए ये राज्य के पतन का लाभ उठाते हैं।

- <u>संघीय विभाजन</u>:

हालांकि सबसे विस्फोटक हौथी- हादी विभाजन इस क्षेत्र में एकमात्र संघर्ष नहीं है। दक्षिण , जो 1990 के संघ से पहले उत्तर से अलग एक स्वतंत्र राज्य था , ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है।

यह दक्षिण बनाम उत्तर संघर्ष कोई नई बात नहीं है। 1918 में ओटोमन साम्राज्य के विघटन के बाद 'उत्तरी' यमन ने स्वतंत्रता प्राप्त की और 1962 तक यमन अरब गणराज्य की स्थापना हुई। अगले पांच सालों के भीतर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ यमन (दक्षिण में) का गठन किया गया था, 1969 में मार्क्सवादी सत्ता में आए, तब इसे यमन्स पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का नाम दिया गया था। उत्तर और दक्षिण- दोनों यमन ने 1972 में सीमा संघर्ष का सामना किया था। यह संघर्ष अरब लीग के बीच- बचाव के बाद युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ। यह युद्ध विराम ज्यादा समय तक नहीं चला। 1979 में उत्तरी और दक्षिण के बीच फिर से लड़ाई शुरू हुई, जिसके अंत में एकीकरण के प्रयासों को फिर से शुरू किया गया। मई 1990 में अली अब्दुल्ला सालेह के राष्ट्रपति बनने के साथ यमन गणराज्य के रूप में दोनों यमन एक हुआ। लेकिन इन दोनों राज्यों के बीच तनाव के नतीजे में 1994, 1997 और 2003 में बार-बार गृहयुद्ध हुए।

दक्षिणी आंदोलन, जो अल-हिराक भी कहलाता है , मूलतया सात अलग- अलग समूहों का एक समन्वित गठबंधन है। वे केंद्र सरकार के विरोध और दक्षिण के लोगों के लिए समान अवसरों की मांग में एकजुट हैं।

फिर भी दक्षिणी आंदोलन के प्रत्येक पक्ष ने अपने स्वयं के राजनीतिक एजेंडे को लागू करने की कोशिश की। इसमें उनके बीच एकजुटता का अभाव निहित है और इसलिए उत्तर में बैठी राजनीतिक सत्ता पर वे दबाव नहीं डाल सकते हैं।

हादी के अन्य मुख्य समर्थक मुस्लिम ब्रदरहुड जुड़े अल-इस्ला पार्टी और नागरिक समाज के नेता हैं।[12] हालांकि दक्षिणी आंदोलन के लोगों को विशेष रूप से 1994 के युद्ध में बाद की भूमिका के कारण अल-इस्ला पार्टी के उत्तरी नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। उन्हें हादी पर भी शक है, जो उत्तर के साथ निरंतर एकता का समर्थन करने वाले एक सौंदर्यवादी हैं। इस प्रकार, इन समूहों में आपसी विद्वेष है, जो कि हौथियों और सालेह को संयुक्त रूप से लड़ने में बाधक होगा।

हौथी समर्थक और पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के गठबंधन के बीच तनाव भी बढ़ रहा है। दोनों चाहते हैं कि सत्ता में कोई भी हो , शक्ति-बंटवारे के लिए जितना संभव हो कम से कम समझौता करने को तैयार है।

- <u>एक क्षेत्रीय छद्म युद्ध?</u>

यमन में विभिन्न गुटों के बीच आंतरिक सत्ता संघर्ष को ग्रहण लग गया और जब सऊदी अरब ने मार्च 2015 में जीसीसी गठबंधन समर्थित ऑपरेशन अल- हज़म स्ट्रॉम के माध्यम से सैन्य हस्तक्षेप करने का फैसला किया तो इसे नए सिरे से आकार दिया जाने लगा। ऑपरेशन का मूल उद्देश्य मुख्यतया हवाई हमलों के माध्यम से, "हौथी समर्थकों द्वारा जारी आक्रामकता से यमन और उसके लोगों की रक्षा करना था। "[13] जबकि सऊदी अरब और मिस्र ने जूते प्रदान किए , अमेरिका ने घोषणा की कि वह खुफिया, लक्ष्य साधन और रसद के साथ सहायता करेगा। इस सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य हस्तक्षेप का उद्देश्य मंसूर हादी की बेदखल सरकार को बहाल करना था। चूंकि सऊदी अरब हौथी समर्थक को इस क्षेत्र में ईरानी प्रभाव के विस्तार के एक हिस्से के रूप में देखता है; यमन संघर्ष ने सुन्नी-शिया संघर्ष के आयाम को ईंधन जुगाया और इसे सऊदी अरब तथा ईरान के बीच छद्म युद्ध के रूप में देखा जाता है।

बहरहाल, ऑपरेशन अल-हज़म स्ट्रॉम के एक साल बाद 17 मार्च 2016 को सऊदी अरब ने कहा है कि वह यमन में अपने ऑपरेशन को कम कर रहा है , जबकि 'हवाई सहायता' प्रदान करता

रहेगा। गठबंधन का प्राथमिक कार्य अब यमन सेना बनाने में मदद करना होगा , जिसके लिए गठबंधन सैनिकों की 'छोटी' टीम बनी रहेंगी।[14]

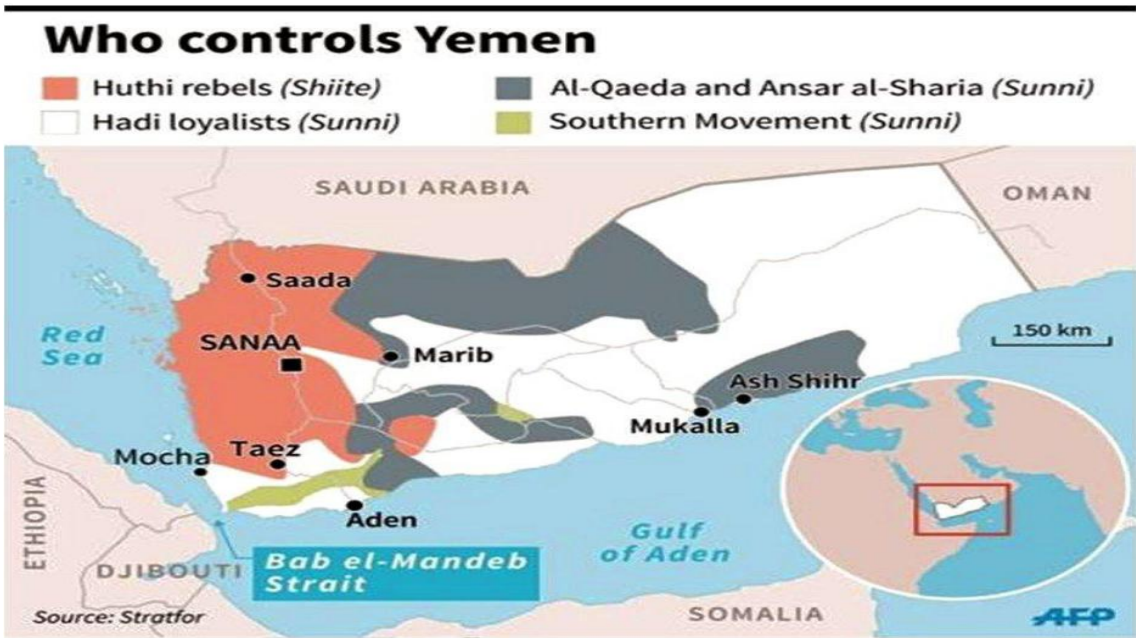

स्रोत: गुगल[15]

आगे की राह

शांति-स्थापना प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम आत्म विश्वास-निर्माण सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई जैसे उपायों के सामान्य रूपरेखा के तहत निर्मित एक व्यापक समझौता होगा ; लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता के वितरण में सभी बाधाओं को खत्म करना होगा। बिजली और पानी की आपूर्ति में कटौती और अस्पतालों और एम्बुलेंसों पर हमले जैसे अन्य कार्य बंद होने चाहिए।

एक महत्वपूर्ण कदम संयुक्त राष्ट्र सत्यापन और निरीक्षण तंत्र (यूएनवीआईएम) की स्थापना है, जिसका उद्देश्य खाद्य, ईंधन और दवाओं जैसे वस्तुओं के वैध वाणिज्यि क आयात में तेजी लाना था। यमन बंदरगाहों के माध्यम से तंत्र ने ईंधन और भोजन के आयात में वृद्धि की है।[16]

इन कदमों के साथ यमन के आर्थिक जीवन को फिर से शुरू होना चाहिए , जो बदले में हौथी सिपहसालारों द्वारा काला- बाजारी व्यापार को समाप्त करने की मांग कर ता है। काला-बाजार न केवल खाद्य वस्तुओं और सहायता का होता है; बल्कि अवैध छोटे हथियारों और हल्के हथियारों का भी होता है।[17]

बच्चों की भर्ती भी बंद होनी चाहिए और जिन लोगों को जबरन लिया गया था , उन्हें उनकी रैंक से मुक्त किया जाना चाहिए। अपने समुदायों में पुन :एकीकरण सत्ता के लिए एक कठिन कार्य होगा , लेकिन यह एक ऐसा काम भी नहीं है जिससे बचा जाना चाहिए।

इस साल जनवरी में जो परामर्श की प्रक्रिया होनी थी , वह अनिश्चित काल के लिए टल गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। परस्पर विरोधी दलों को यह महसूस करना होगा कि राजनीतिक स्थिरता औ र राष्ट्र-राज्य की विफलता का अर्थ है आतंकवादी संगठनों (जैसे अल- कायदा का यमनी सहयोगी और आईएस) जैसे गैर-राज्य संस्थानों के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार करना होगर। इससे किसीका कोई लाभ नहीं होगा।

दक्षिण और उत्तर यमन के संघर्ष से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीति की भी आवश्यकता है। चूंकि संघर्ष की राजनीतिक और सामाजिक- आर्थिक जड़ें दक्षिण यमन में हैं , इसलिए उनकी स्थिति में आर्थिक और वित्तीय सुधार के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। राजनीतिक सुधार, अधिक पारदर्शिता और भ्रष्टाचार का अंत आवश्यक कदम हैं, लेकिन इन कार्यों की तुलना में कहीं आसान है।

यमन की राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सभी हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता होगी और इस प्रक्रिया को जारी रखने के तरीकों में से एक हैखाड़ी सहयोग पहल , इसका कार्यान्वयन तंत्र राष्ट्रीय संवाद सम्मेलन के परिणामों के अनुरूप है। 2011 में जीसीसी पहल ने जिस गतिरोध की बात को स्वीकार किया था, वह आज भी कायम है और यही यमन वासी की परेशानी का सबब है। इसलिए जीसीसी पहल के कार्यान्वयन की वापसी बहुत महत्वपूर्ण है। इस में एक नया संविधान का निर्माण और

समय पर आम चुनाव कराना शामिल है। यमन वासियों और , दरअसल, हौथी समर्थकों को समझना चाहिए कि दुनिया में कोई भी संविधान पूरी तरह से सही नहीं है। नए संविधान में पुराने की कमियों से सीखने की एक गुंजाइश है और हर संविधान समय के अनुसार विकसित हो सकता है। इसलिए किसी भी संविधान की एकदम से अवहेलना करना उचित नहीं है। न ही सरकार और सुरक्षा संस्थानों पर जबरन कब्जा उचित है।

एक और तथ्य को भी याद रखना जरूरी है और वह यह कि सऊदी अरब ने यमन के संकट में गहरी दिलचस्पी ली है। हालांकि , भले ही सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन का दावा है कि प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रपति हादी की सरकार की बहाली है, लेकिन सऊदी अरब को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई नागरिक हताहत न हो। बम विस्फोट का शिकार हुए नागरिकों की संख्या को देखते हुए लगता है यह एक कठिन कार्य है।[18]

एक स्थिर यमन क्षेत्रीय हित में काम करता है , और फिर भी, जीसीसी राज्य क्या कर सकते हैं या करने की इच्छा रखते हैं , स्पष्ट रूप से इसकी सीमाएं हैं। हालांकि वे चर्चा के लिए मंच प्रदान कर सकते हैं (जैसे कि सऊदी अरब ने किया था), ऐसा लगता है कि केवल अंतरराष्ट्रीय शक्तियां दोनों पक्षों की सहूलियत के लिए एक सामान्य टेबल पर मिलने के लिए राजी करने में सक्षम हो सकती हैं (जैसे स्विट्जरलैंड ने किया था [19]। फिर भी , अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी अंत ररा ष्ट्रीय ताकतें यमन की स्थिति के प्रति एक नाज़ुक रवैया रखती हैं। इसमें बदलाव होना चाहिए , क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने सभी संबंधित पक्षों से बातचीत में शामिल होने और वैध शिकायतों को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है, लेकिन मांग को कार्रवाई में बदलने की रणनीति का अभाव है।

फिर भी आगे देखने पर लगता है, इसमें लिप्त पार्टियों के बीच एक खुला संवाद शामिल है। ऐसा हुआ तो; लेकिन जैसा कि देखने में आया , यमन में शांति बनाए रखने की प्रारंभिक शांति- प्रक्रिया की तुलना में यह कहीं अधिक कठिन रहा है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय संवाद सम्मेलन और जीसीसी पहल के माध्यम से शांति स्थापना के प्रयासों के प्रारंभिक दौर जनवरी 2014 में एनडीसी के भीत र हौथी प्रतिनिधियों की हत्या तक सफल बताया जा सकता है। दिसंबर 2015 में स्विट्जरलैंड में शांति स्थापना के लिए एक और प्रयास किया गया , जिसके परिणामस्वरूप यमन सरकार और उसके सैन्य और

राजनीतिक विरोधियों के बीच 'रचनात्मक वार्ता' हुई। भविष्य में वार्ता को फिर से शु रू करने और शत्रुता को समाप्त करने और मजबूती के लिए संवाद ने आधार प्रदान किया।[20] बहरहाल, फरवरी 2016 में यह शांति स्थापना कर ने वाला चरण को सनाया के करीब रणनीतिक सैन्य अड्डे फरदत निहम को लेकर युद्ध से एक झटका लगा। हौथी समर्थकों ने सऊदी में स्कड मिसाइलों को भी लॉन्च किया था, इससे तनाव में इजाफा हुआ।[21]

इसलिए, सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है सभी दलों को अपनी बाहें पसारे और हर तरह का राजनीतिक मोर्चा अपने दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता हैं। सबको यह याद रखना चाहिए कि इस तरह के संघर्षों में तथाकथित 'विजेता' के विचार का अब कोई मायने नहीं रह गया है , क्योंकि हर कोई हार रहा है और सबसे बड़ा शिकार यहां बेगुनाह नागरिक हैं।

निष्कर्ष:

राष्ट्रपति अब्द रब्बो मंसूर हादी के शिथिल नेतृत्व में पूर्व राष्ट्रपति सालेह के साथ मिलकर में यमन संघर्ष, संक्षेप में, हौथी विद्रोहियों और सैन्य इकाइयों को विरोधियों के विविध मिश्रण के खिलाफ खड़ा किया। मंसूर हादी को एक सऊदी गठबंधन का समर्थन है, बदले में उसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन प्राप्त है। इस प्रकार, यमन में राजनीतिक अनिश्चितता की एक ऐसी स्थिति है , जहां हौथी समर्थक मोहम्मद अली अल-हौथी के नेतृत्व वाली सरकार का दावा करता हैं ; जिसे संयुक्त राष्ट्र , अमेरिका और जीसीसी गठबंधन वाले देशों की मान्यता प्राप्त नहीं है। जीसीसी गठबंधन सैन्य ऑपरेशन अल-हज़म स्ट्रॉम (मार्च 2015 में) के साथ यमन गृहयुद्ध में उतर गया; अभी भी इसका कोई अंत नजर आता नहीं लगता है।

पश्चिम एशियाई क्षेत्र में चल रही ढेर सारी लड़ाइयों के बीच यमन युद्ध भी महत्वपूर्ण है। 2700 से अधिक नागरिक[22] मुख्यतया दोनों पक्षों के हवाई हमलों से मारे गए हैं; वहीं बड़ी संख्या में विस्थापित हुए हैं। इससे विकट मानवीय संकट शुरू हो गया है, जो जल्द ही अकाल और शरणार्थी प्रवाह में तब्दील हो सकता है; इस क्षेत्र को यह और भी अस्थिर करेगा। अंत रराष्ट्रीय दबाव और भी तीव्र होगा। क्षेत्रीय अभिकर्ता, खासतौर पर सऊदी अरब , एक ऐसे युद्ध में फंसता दिखता है , जिसकी शुरूआत तो आसान

थी, लेकिन खत्म करना कहीं अधिक कठिन है। हौथी ब्लॉक और हाडी सरकार बात करने के लिए तैयार दिखते हैं, लेकिन शांति की शर्त युद्धोन्माद पर लगाम , सुलह और समझौते के लिए खुद को प्रतिबद्ध नहीं करना चाहते हैं।

युद्ध समाप्त करने के लिए वार्ता की आवश्यकता होगी , जिसमें सुरक्षा व्यवस्था मसलन- शहरों से सैन्य बल की वापसी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2216 और जीसीसी पहल की राजनीतिक प्रक्रिया की वापसी; शामिल हो। इसमें अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व का अंतरिम समझौता भी शामिल होना चाहिए या, दूसरे शब्दों में, क्षेत्रीय अभिकर्ताओं को तुरंत सैन्य कार्रवाई को रोकना चाहिए और घरेलू पार्टियों को व्यापक रूप से राष्ट्रपति या राष्ट्रपति परिषद के लिए सहमत होने में मदद करनी चाहिए। इतना तो तय है कि इस तरह की वार्ता तक पहुंचने में समय लगेगा , लेकिन यमन वासियों के पास इतना समय नहीं है। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में मान वीय सहायता और वाणिज्यिक सामान पहुंचाने के समझौते को सुनिश्चित करना तत्काल प्राथमिकता होनी चाहिए।

ऐसा लगता है कि सऊदी अरब की गठबंधन की पीठ और गठबंधन सैनिकों के साथ ब्रिगेडियर जनरल अहमद अल-अससेरी के हाल ही में जारी बयान के साथ एक कदम आगे बढ़ना है , जिसमें कहा गया है कि 'यमन में बड़ी लड़ाई लगभग समाप्त हो रही है ... (और) अगला चरण स्थिरता को बहाल करने और देश के पुनर्निर्माण का एक चरण है '।[23] अंत में, यमन में शांति की बहाली क्षेत्र के लिए फायदेमंद होगी और पश्चिम एशिया में चल रहे अन्य संकटों का हल निकालने में यह ए क समझ भी पैदा करेगा।

***

**जेठू एल्ज़ा चेरियन चाको इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स , नई दिल्ली में एक रिसर्च इंटर्न हैं। आलेख में व्यक्त किए गए विचार शोधकर्ता के हैं, काउंसिल के नहीं।*

अंत टिप्पण:

---

1 These sea lanes are already prowled by Somali pirates and the Coast Guard of Yemen has been part of international efforts to protect shipping in the region.

2 https://www.google.co.in/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPnr_IksrLAhVDE5QKHaeUDacQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fsyrianfreepress.wordpress.com%2F2016%2F02%2F21%2Falmandeb-socotra%2F&psig=AFQjCNHXVH-xampdzcNDlTywxXhYEzvQKw&ust=1458386836541858, Accessed on 28/01/2016.

3 "UN refugee agency warns over perilous Horn of Africa sea crossings" (2016) http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53047#.VqnChtJ97cs, Accessed on 28/01/2016.

4 "Situation of Human Rights in Yemen: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights" (2015), p14, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/30/31, Accessed on 27/01/2016

5 "Saudi-led air strike targets Yemen hospital: Saba news agency" (2016) http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-idUSKCN0UP1DT20160111, Accessed on 28/01/2016.

6 "Statement attributable to the Spokesman for the Secretary-General on Yemen" (2015) http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=8493, Accessed on 27/01/2016.

7 "Statement of the Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Stephen O'Brien" to the Security Council on Yemen, 16 February 2016, file:///E:/RI/yemen/2a_hrc_30_31.pdf, Accessed on 19/02/2016.

8 http://www.securitycouncilreport.org/chronology/yemen.php, Accessed on 27/01/2016.

9 The World Factbook, US Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html, Accessed on 28/01/2016.

10 Charles Schmitz (2014), MEI Policy Paper 2014-1: Yemen's National Dialogue http://www.mei.edu/sites/default/files/publications/Charles%20Schmitz%20Policy%20Paper.pdf, Accessed on 15/02/2016.

11 The World Factbook, US Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html, Accessed on 28/01/2016.

12 Civil society leaders are those who believed in the promise of the Rule of Law and the implementation of the outcomes of the National Dialogue Conference.

13 United Nations Security Council Resolution 2216 (2015) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2216(2015), Accessed on 27/01/2016.

14 "Major Fighting in Yemen coming to an end: Saudi coalition spokesman" (2016), http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-idUSKCN0WK0TR, Accessed on 18/03/2016.

15 http://libertyunyielding.com/wp-content/uploads/2015/03/Yemen-coalition-map-2.jpg, Accessed on 27/01/2016.

[16] "Statement of the Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Stephen O'Brien" to the Security Council on Yemen, 3 March 2016, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/USG%20OBrien%20to%20SecCo%203Mar2016.pdf, Accessed on 18/03/2016.

[17] The Saudi imposed blockade on Yemen seems to have had only a limited effect. The blockade seems not to have prevented Saleh and the Houthis from acquiring fuel and military supplies.

[18] "The Situation in the Middle East": United Nations Security Council Meetings Record S/PV.7622 (2016), http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_7622.pdf, Accessed on 18/03/2016.

[19] "The Situation in the Middle East": United Nations Security Council Meetings Record S/PV.7596 (2015), http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_7596.pdf, Accessed on 28/01/2016.

[20] "The Situation in the Middle East": United Nations Security Council Meetings Record S/PV.7622 (2016), http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_7622.pdf, Accessed on 18/03/2016.

[21] "Yemen: Is Peace Possible?": International Crisis Group Report 9 February 2016 (2016), p4, http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Yemen/167-yemen-is-peace-possible, Accessed on 16/02/2016.

[22] "The Situation in the Middle East": United Nations Security Council Meetings Record S/PV.7622 (2016), http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_7596.pdf, Accessed on 18/03/2016.

[23] "Major Fighting in Yemen coming to an end: Saudi coalition spokesman" (2016), http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-idUSKCN0WK0TR, Accessed on 18/03/2016.